भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

<u>अप्रैल, 2022 के लिए मासिक सारांश</u>

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 अमृत काल में सिद्धि का संकल्प थीम के साथ- 24 अप्रैल, 2022 को मनाया गया था । राष्ट्रीय समारोह का आयोजन जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के अंतर्गत पल्ली ग्राम पंचायत में किया गया था और माननीय प्रधान मंत्री ने इसकी शोभा बढ़ाई थी।

2. विभिन्न स्तरों पर 322 पंचायतों को पंचायतों में उनके अच्छे विकास कार्यों के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) से सम्मानित किया गया:

(a) 29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में 29 ग्राम पंचायतों (जीपी) / ग्राम परिषदों (वीसी) को बाल-हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार

(b) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 29 ग्राम पंचायतों/ परिषदों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार

(c) 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 27 ग्राम पंचायतों/कुलपतियों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार

(d) 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 237 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार [(जिला पंचायत: 28); (ब्लॉक पंचायत: 53); (GPs/VCs: 156)]

3. प्रधानमंत्री द्वारा एनपीआरडी-2022 के अवसर पर पुरस्कार विजेता पंचायतों को सहायता अनुदान के रूप में 44.70 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। 7 राज्य अर्थात; असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को भी अपने-अपने राज्यों में ग्रामीण स्थानीय-स्व-सरकार के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ई-पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

4. स्वतन्त्रता के 75वें वर्ष में मनाए गए एनपीआरडी-2022 के हिस्से के रूप में, माननीय प्रधान मंत्री ने पल्ली ग्राम पंचायत का दौरा किया और पल्ली पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उसके बाद देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की कई विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। माननीय प्रधान मंत्री ने 18 दिनों के रिकॉर्ड समय में पल्ली ग्राम पंचायत में निर्मित 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया और कहा कि यह कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की दिशा में ग्राम पंचायत द्वारा उठाया गया पहला कदम था। उन्होंने अमृत सरोवर पहल की भी शुरुआत की। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह, डॉ. जितेंद्र सिंह और श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने पल्ली ग्राम पंचायत के कुछ लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड सौंपे।

5. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। संबंधित पुरस्कार प्राप्त पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करने के लिए राज्य और जिला मुख्यालय स्तर पर पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किए गए ।

6. आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) मनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने "संपूर्ण-समाज" और "संपूर्ण-सरकार" की परिकल्पिना के साथ प्रतिष्ठित सप्ताह (11 अप्रैल - 17 अप्रैल, 2022) के दौरान विषयगत सम्मेलनों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण की दिशा में सभी हितधारकों के विचारों, तैयारियों, तकनीकी हस्तक्षेपों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अत्याधुनिक अंतर्दृष्टि के अभिसरण के साथ "पंचायतों के नव निर्माण का संकल्पोत्सव" विषय की केंद्रीयता के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। यह एक पंचायती राज संस्थाएं, और इन एसडीजी को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाएं जो

कार्रवाई कर सकती हैं, साथ ही साथ समर्थन आधार और संसाधन जो जुटाए जा सकते हैं के माध्यम से किया जाएगा।

7. भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू ने 11 अप्रैल, 2022 को 'सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत इस अवसर पर केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और बारह राज्यों के पंचायती राज मंत्री उपस्थित थे। सप्ताह भर चलने वाले सम्मेलनों में पूरे देश से लगभग 5,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें पंचायती राज संस्थानों के लगभग 3,000 निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल थे। सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का प्रमुख आकर्षण सतत लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन था, जहां ग्रामीण स्थानीय स्व-सरकार की भूमिका और उनकी उपलब्धियों के साथ-साथ व्यापक नौ विषयों के तहत 17 एसडीजी की प्राप्ति के लिए गहन अनुभव साझा सत्र हुए। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को 2030 तक एसडीजी की प्राप्ति में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराना था ताकि सुशासित और लैंगिक समानता, गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका, स्वस्थ, बच्चों के अनुकूल, पानी पर्याप्त, स्वच्छ और हरा, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा व सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव सुनिश्चित किए जा सके।

8. पहली बार संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और यूएनईपी, एफएओ, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी खड़गपुर, उन्नत भारत अभियान, आईआरएमए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जेएचपीआईईजीओ, हेल्पएज इंडिया, वाटरएड भारत जैसे डोमेन विशेषज्ञों सहित सभी हितधारक सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पीआरआई का समर्थन कैसे किया जा सकता है, इस पर समग्र रूप से विचार-विमर्श करने के लिए एक साझा मंच पर आए ।

9. इन सम्मेलनों के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख गतिविधियाँ जैसे माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा एलएसडीजी लोगो, भारत सरकार के 21 मंत्रालयों के 26 विभागों के सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित 9 विषयगत क्षेत्रों पर संयुक्त सलाह का संग्रह, 14 भारतीय भाषाओं में ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग के लिए विषयगत प्रस्तुतियों का संग्रह को जारी करना, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए और डब्ल्यूएचओ के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और श्री यासुमासा किमुरा, देश प्रतिनिधि, यूनिसेफ इंडिया द्वारा बाल अनुकूल पंचायतों पर सर्वोत्तम प्रथाओं के संग्रह का विमोचन, महिला अनुकूल

जीपी पर प्रशिक्षकों का एक प्रशिक्षण मैनुअल, लैगिंक समानता पर आधारित कानूनों पर ब्रोशर और पंचायतों की भूमिका पर दो पोस्टर का विमोचन परिवार नियोजन तक पहुंच में सुधार और मातृ स्वास्थ्य में सुधार और ब्रेल में प्रशिक्षण सामग्री का विमोचन भी सप्ताह भर चलने वाले समारोह के दौरान हुआ। इसके अलावा सुशासन पर सम्मेलन- 'सुशासन- सुगमता से सम्पंता' और "स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि (सप्ताह के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के ओएसआर)" का भी आयोजन किया गया।

10. 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-टर्मिनस) के कार्यान्वयन के लिए 3700 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से और 2211 करोड़ रुपये के राज्य के हिस्से सहित कुल 5911 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना को 13.04.2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

11. संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) पहलों पर विचार-विमर्श करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ 04.04.2022 और 18.04.2022 को विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचे (एनसीबीएफ) को संशोधित करने के लिए गठित पंचायती राज मंत्रालय, क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) और विशेषज्ञ समूह के बीच परामर्श 22 अप्रैल, 2022 को केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, त्रिशूर, केरल में आयोजित किया गया था।

12. विशिष्ट सप्ताह समारोह के दौरान हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए 29 अप्रैल को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों- यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए और उन्नत भारत अभियान के साथ एक अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई थी।

13. आज की तारीख में, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता सहित घरेलू कचरे के प्रबंधन और उपचार, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन आदि सहित ओडीएफ स्थिति का रखरखाव आदि और बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए 15वें वित्तस आयोग के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों/पारंपरिक स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 37300.33 करोड़ रुपये (आवंटन का 83.07%) जारी किए गए हैं।

14. ग्राम पंचायतों को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा स्वराज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए

सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में 28 अप्रैल, 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

15. स्वामित्व योजना के तहत गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले गांव के गृह मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, त्रिपुरा और असम की स्वायत्त जिला परिषद सहित 31 राज्य / केंद्रशासित प्रदेश योजना शामिल हो चुके हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, असम और उत्तरी कछार हिल्स, असम की जिला स्वायत्त जिला परिषद एवं सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर दिनांक 4 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 19 अप्रैल 2022 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और तेलंगाना सरकार के बीच योजना के कार्यान्वयन के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर पायलट आधार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, दिनांक 26 अप्रैल 2022 को भारतीय सर्वेक्षण और दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 30.04.2022 तक, 1,34,567 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हो चुकी है और 137 जिलों के सभी आबादी गांवों में ड्रोन-सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। हरियाणा, गोवा, दमन और दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के सभी आबादी गांवों में ड्रोन ने उड़ान भरी।

16. पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध वित्त के प्रबंधन के लिए, पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों को सख्ती से राजी करा रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत (जीपी) पंजीकरण के लिए राज्यों से प्रयास कर रहा है। पिछले साल यानी 2021-22 में 53% ग्राम पंचायतों ने अपनी ईयर बुक बंद कर दी हैं। अब तक, 2,35,873 पंचायती राज संस्थसनों ने ईग्राम स्वाराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) पर ऑन-बोर्ड हो चुकी हैं। अप्रैल 2022 के महीने में 1,98,528 पंचायती राज संस्थसनों ने XV वित्त आयोग अनुदान के साथ किए गए खर्च के लिए ईजीएसपीआई का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन किया है।

17. इसके अलावा, पीआरआई स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज में रसीद प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए 'पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन' की प्रक्रिया में है। 23 राज्यों ने स्टेट ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन की इस कवायद को पूरा कर लिया है।

18. मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत एक एप्लीमकेशन - ऑडिटऑनलाइन भी शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा देता है और आंतरिक और बाह्य ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। वर्ष 2019-20 के लिए, 27 राज्यों (केरल सहित) ने पहले ही 7,959 ऑडिटर, 2,57,727 ऑडिटी को पंजीकृत कर लिया है और 14वें वित्त आयोग के खातों की लेखापरीक्षा के लिए 1,32,780 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा योजना तैयार की है। एप्लीाकेशन पर राज्यों द्वारा 11,64,233 टिप्पणियां दर्ज की गई हैं और वर्ष 2019-20 के लिए 1,09,633 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 1,78,054 ग्राम पंचायतों, 2,396 ब्लॉ6क पंचायत और 187 जिला पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई है। राज्यों द्वारा 13,15,614 टिप्परणियां दर्ज की गई हैं और कुल 109,046 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं, जिनमें से 1,07,249 ग्राम पंचायतों द्वारा, 1691 ब्लॉ क पंचायत द्वारा और 106 जिला पंचायतों द्वारा तैयार की गई हैं।

19. 1 अप्रैल, 2022 तक मंत्रालय के पास 59 शिकायतें/याचिकाएं लंबित थीं और अप्रैल माह के दौरान 285 (अर्थात 270 ऑनलाइन + 15 वास्तकविक) शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। कुल 344 (अप्रैल में प्राप्त 285 + पिछले महीने से 59 अग्रेषित) में से 239 शिकायतों / याचिकाओं का अप्रैल में निपटारा किया गया और 105 को 1 मई, 2022 तक आगे बढ़ाया गया।

20. अप्रैल 2022 के दौरान, ई-ऑफिस सिस्टम में 88 ई-फाइलें खोली गईं, जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of April, 2022

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realize the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. National Panchayati Raj Day 2022 with the theme - ***Amrit Kaal Mein Siddhi Ka Sankalp*** was celebrated on 24th April, 2022. The National function was organized at Palli Gram Panchayat under Samba District of UT of Jammu & Kashmir and was graced by the Hon'ble Prime Minister.

2. 322 Panchayats at various tiers were conferred with National Panchayat Awards 2022 (Appraisal Year 2020-21) in the following categories for their good developmental works in the Panchayats:

    (a) Child-friendly Gram Panchayat Award to 29 Gram Panchayats (GPs)/ Village Councils (VCs) in 29 States/Union Territories (UTs)
    (b) Gram Panchayat Development Plan Award to 29 GPs/ VCs in 29 States/UTs
    (c) Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar to 27 GPs/ VCs in 27 States/UTs
    (d) DeenDayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar to 237 Panchayats [(District Panchayats: 28); (Block Panchayats: 53); (GPs/VCs: 156)] across 29 States/UTs.

3. Award money of Rs.44.70 crore as grants-in-aid to the Awardee Panchayats was transferred to their bank accounts by the Prime Minister on the occasion of NPRD-2022. 7 States viz; Assam, Chhattisgarh, Karnataka, Odisha, Sikkim, Tripura and

Uttar Pradesh were also conferred with e-Panchayat Puraskar for their outstanding contribution for promotion of digitalisation of rural local-self-government in their respective States.

4. As part of the NPRD-2022, celebrated in the 75th year India's independence, the Hon'ble Prime Minister visited Palli Gram Panchayat and interacted with the elected representatives of Palli Panchayat followed by his address to all the Gram Sabhas across the country. He inaugurated and laid the foundation stone of multiple development initiatives in J&K worth around Rs 20,000 crore. Hon'ble Prime Minister also inaugurated the 500 KW Solar Power Plant constructed in Palli GP in a record time of 18 days and noted that it was the first step taken by the GP towards becoming a Carbon Neutral Panchayat. He also launched the Amrit Sarovar initiative. Lt Governor of Jammu and Kashmir Shri Manoj Sinha, Union Ministers Shri Giriraj Singh, Dr. Jitendra Singh and Shri Kapil MoreshwarPatil were among those present on the occasion. The Prime Minister handed over SVAMITVA cards to some beneficiaries of Palli Gram Panchayat.

5. Special Gram Sabhas were organised across the country to celebrate National Panchayati Raj Day. Award Distribution Ceremonies were also organised at State and District Headquarters level to felicitate and confer the National Panchayat Awards to the concerned awardee Panchayats.

6. To commemorate Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM), the Ministry of Panchayati Raj organised a series of Thematic Conferences during the Iconic Week (11th April – 17th April, 2022), following a "whole-of-society" and "whole-of-government" approach with the centrality of the theme "**Panchayaton ke Navnirman ka Sankalpotsav**" to showcase the convergence of the views, ideas, opinions, preparedness, technological interventions, best practices and cutting-edge insights of all stake-holders towards Localization of Sustainable Development Goals (SDGs) through Panchayati Raj Institutions, and the actions the PRIs can take to achieve these SDGs, as well as the support base and resources that can be mobilized.

7. Hon'ble Vice President of India, Shri M Venkaiah Naidu inaugurated National Stakeholders Conference on 'Localization of Sustainable Development Goals' on 11th April, 2022. Union Minister of Rural Development and Panchayati Raj Shri Giriraj Singh, Union Minister, Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Union Minister of State for Panchayati Raj, Shri Kapil Moreshwar Patil, Union Minister of State for Rural Development Shri Faggan Singh Kulaste and Panchayati Raj Ministers of twelve States graced the occasion. About 5,000 participants from all across the country which included about 3,000 elected representatives and functionaries of Panchayati Raj Institutions attended the week-long conferences. The major attraction of the week-long celebration was National Conferences on localization of Sustainable Goals where intense experience sharing sessions on role of the rural local self-government and their achievements along with way forward for attainment of the 17 SDGs subsumed under broad nine themes took place. The objective was to make the elected representatives aware of their roles and responsibilities in attainment of SDGs by 2030 so as to ensure poverty free and enhanced livelihood, healthy, child friendly, water sufficient, clean and green, self-sufficient infrastructure, socially secured, good governed and gender parity villages.

8. For the first time all stakeholders including inter aliaUN agencies, academic institutions and domain experts such as UNEP, FAO, IIT Delhi, IIT Chennai, IIT Kharagpur, Unnat Bharat Abhiyaan, IRMA, Bill & Melinda Gates Foundation, JHPIEGO, HelpAge India, WaterAid India, came on one common platform to deliberate in a holistic manner on how PRIs could be supported to achieve the objective of Localisation of Sustainable Development Goals (LSDGs).

9. During these conferences, interalia, major activities like release of LSDG logo, Compendium of Joint Advisories on 9 Thematic areas signed by Secretaries of 26 Departments of 21 Ministries of Government of India, compendium of thematic presentations for use by Gram Panchayats in 14 Indian languages by Hon'ble Vice President, signing of Joint Statement of Understanding with UN agencies UNICEF, UNDP, UNFPA and WHO were undertaken. Release of compendium of best practices on Child friendly Panchayats by Secretary, MoPR and Mr. Yasumasa Kimura, Country Representative, UNICEF India, release of one Training of Trainers Manual on Women Friendly GPs, brochure on gender based laws and two posters on role of Panchayats in improving access to family planning & in improving maternal health and release of training material in Braille also took place during the week long AKAM celebrations.In addition conferences on Good Governance- 'Sushasan- Sugamta se Sampanta' and "Augmentation of Own Source Revenues (OSR) of Rural Local Bodies were also organized during the week.

10. Centrally Sponsored Scheme of Revamped RGSA,with a total outlay of Rs.5911 crore including Central Share of Rs.3700 crore and State share of Rs.2211 crore, for implementation between 2022-23 to 2025-26 (co-terminus with XV Finance Commission period) was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 13.04.2022.

11. Consultations with Capacity Building Commission (CBC) were held on 04.04.2022 and 18.04.2022 to deliberate upon Capacity Building & Training (CB&T) initiatives under the Scheme of Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA). Further, consultation between MoPR, Capacity Building Commission (CBC) and Expert Group constituted for revising National Capacity Building Framework (NCBF) was held on 22nd April, 2022 in Kerala Institute of Local Administration, Thrissur, Kerala.

12. A follow up meeting was held with UN Agencies- UNDP, WHO, UNFPA, and Unnat Bharat Abhiyaan under the Chairmanship of Secretary, MoPR on 29th Aprilto take forward the commitment of the Joint Statement of Understanding signed during Iconic Week celebration.

13. As on date, XV FC grants to the tune of Rs. 37300.33 crore (83.07 % of allocation) for FY 2021-22 has been released by the Ministry of Finance to the States for Rural Local Bodies/Traditional Local Bodies for improving basic services including supply of drinking water, rain water harvesting, water recycling, sanitation & maintenance of ODF status including management and treatment of household waste, human excreta and faecal sludge management, etc.

14. A meeting was held on 28thApril, 2022 under chairmanship of Secretary, Panchayati Raj to discuss various aspects of Gram Urja Swaraj aimed at making Gram Panchayats self- sufficient in energy through implementation of renewable energy projects. The meeting was attended by representatives of Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), IIFCL Projects Ltd and Central Electronics Ltd (CEL).

15. Under SVAMITVA Scheme aiming to provide the 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of Property cards to the Property owners, 31 States/UTs are on-boarded on Scheme including Autonomous District Council of Tripura and Assam. A tripartite MoU among Survey of India (Sol), Govt. of Assam and North Cachar Hills, District Autonomous District Council of Assam was signed on 4thApril 2022. Another MoU between Survey of India and Govt. of Telangana for the implementation of Scheme on Pilot basis was signed on 19 April 2022. Subsequently, MoU between Survey of India and Delhi was signed on 26 April 2022. As on 30.04.2022, drone flying has been completed in 1,34,567 villages and drone-survey completed in all inhabited villages of 137 districts. Drone flying saturated in all inhabited villages of Haryana, Goa, Daman& Dadra and Nagar Havelli, Puducherry, Andaman & Nicobar and Lakshadweep.

16. For management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. In the last year i.e. 2021-22, 53% GPs have closed their year books. So far, 2,35,873 PRIs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). In the month of April 2022- 1,98,528 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred with XV Finance Commission Grant.

17. Further, for strengthening the accountability and transparency at the PRI level, MoPR is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. 23 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

18. The Ministry has also rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For the year 2019-20, 27 States (including Kerala) have already registered 7,959 Auditors, 2,57,727 Auditees and prepared Audit Plans of 1,32,780 GPs for Auditing 14th Finance Commission accounts. 11,64,233 observations have been recorded by States on the application and 1,09,633 audit reports have generated for the year 2019-20. For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 1,78,054 GPs, 2,396 BPs and 187 ZPs. 13,15,614 observations have been recorded by States and total 109,046 audit reports have been generated out of which 1,07,249 by GPs, 1691 by BPs and 106 by ZPs have been generated.

19. There were 59 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st April, 2022 and 285 (i.e. 270 online + 15 physical) grievances/ petitions were received during the month of April. Out of total 344 (285 received in April + 59 carried forward from last

month), 239 grievances/petitions were disposed in April and 105 were carried forward as on1st May, 2022.

20. During April 2022, 88 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****